नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन

63 वॉ वार्षिक अधिवेशन

31 अगस्त एवं 01 सितम्बर 2010 , लखनऊ

प्रस्ताव

नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन का 31 अगस्त एवं 1 सितम्बर 2010 को लखनऊ में आयोजित यह 63वॉ वार्षिक अधिवेशन ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन द्वारा विभिन्न कोटियों के रेल कर्मचारियों की समस्याओं ,के समाधान के लिए किये जा रहे गंभीर प्रयासों के लिए फेडरेशन के नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता है। ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के सतत् प्रयास से विगत महीनों में अनेको महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ रेलकर्मियों को हासिल हुई जो नीचे उल्लेखित है :-

सभी ग्रुप डी कर्मचारियों को 1.1.2006 से पी बी –1 में रुपये 1800 का ग्रेड पे , सभी कारखाना तथा उत्पादन इकाइयों के कर्मचारियों को बढ़ी दरों पर प्रति घंटा इन्सेन्टिव बोनस का भुगतान, वेतन विसंगति कमेटी तथा कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी का गठन ,टेलीफोन आपरेटरों , मंडल कैशियरों , कंसोल आपरेटरों , उधान निरीक्षकों , वेलफेयर इंसपेक्टर, पसर्नल इंसपेक्टर तथा सांख्यिकी निरीक्षको को रुपये 4200 की जगह रुपये 4600 का ग्रेड पे , चाइल्ड एडाप्शन लीव 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन , कार्यरत पति तथा पत्नी की एक ही स्टेशन पर तैनाती , रेल दुर्घटना में कर्मचारियों की मृत्यु पर 5 लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपयें का नगद भुगतान ,राष्ट्रीय अवकाश भत्ते का भुगतान समस्त ग्रुप 'सी' एवं 'डी' कर्मचारियों को कराने का प्रावधान इत्यादि के लिए नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन का यह अधिवेशन ए. आई. आर. एफ. को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है।

यह अत्यन्त खेद का विषय है कि माननीय रेलमंत्रियों द्वारा लगातार, विभिन्न स्तरों पर रेलों का निजीकरण न करने की सार्वजनिक घोषणा के बावजूद अनेकों विभागीय कार्यो को , येन–केन प्रकारेण, "आउटसोर्सिंग" के नाम पर निजी हाथों में सौपने का कार्य पिछले दरवाजे , से हो रहा है, जिसके प्रति यह अधिवेशन गंभीर चिंता व्यक्त करता है । जहॉ रेलों का संरक्षित संचालन रेल उपभोक्ताओं के हित में एवं रेल उद्योग की स्वच्छ छवि बनाये रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है , वहीं उत्तर रेलवे में *"संरक्षा कोटियों "* में लगातार चली आ रही हजारों रिक्तियॉ, रेल संरक्षा के लिए खतरे का मुख्य कारण बनती जा रही हैं और नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन द्वारा विभिन्न स्तरों पर किये जा रहे सतत् प्रयासों के बावजूद , निकट भविष्य में इन्हे भरने का कोई ठोस उपाय दृष्टिगोचर नही हो पा रहा है, जो इस अधिवेशन के लिए एक गंभीर चिंतन का विषय है।

समस्त कामगार वर्ग एवं रेल कर्मचारी महंगाई की मार से त्रस्त है और इस पर अंकुश लगाने मे भारत सरकार के पूर्णतः विफल रहने के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए, यह अधिवेशन अपेक्षा करता है कि इस दिशा में त्वरित कार्यवाही करके इससे शीघ्र ही निजात दिलायी जायेगी।

ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन द्वारा *दिनांक 31.8.2009* तक खाली पड़े, सेलेक्शन तथा नान– सेलेक्शन, पदों पर बिना लिखित एवं मौखिक परीक्षा के ,केवल बेंचमार्किंग के साथ वरीयता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति कराये जाने के ऐतिहासिक फैसले को *दिनांक 31.12.2011* तक बढ़वाये जाने के प्रति यह अधिवेशन ए. आई.आर.एफ के नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करता है , क्योकि इससे लाखों रेल कर्मचारी लाभान्वित होगें।

राष्ट्रीय अवकाश भत्ता के भुगतान के मामले में वेतन की उच्चतन सीमा को समाप्त कराकर , सभी कर्मचारियों को इसकी पात्रता में शामिल कराये जाने के लिये यह अधिवेशन ए. आई.आर.एफ. के नेतृत्व का आभार प्रकट करता है। इस फ़ैसले से तमाम रनिंग कर्मचारियों के साथ–सथ हजारों रेल कर्मियों को भी लाभ मिला।

भारतीय रेलों की खान–पान सेवायें विगत वर्षो मे आई. आर. सी. टी. सी. के माध्यम से अनियंत्रित निजी हाथों में सौपने का कार्य किया गया जिससे गुणवत्ता में दिन प्रतिदिन आ रही गिरावट के कारण भारतीय रेलों की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फडरेशन द्वारा लगातार खान–पान सेवाओं को पुनः विभागीय सेवाओं के अर्न्तगत लाये जाने की मांग की जा रही थी , जिसके परिणामस्वरुप वर्तमान रेलमंत्री के निर्देश पर पुनः इन सेवाओं को रेलवे की विभागीय खान–पान सेवा में परिवर्तित करने के आदेश जारी किये गये है , जिसके लिए यह अधिवेशन ए. आई.आर.एफ तथा रेलमंत्री के प्रति आभार प्रकट करता है।

देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरुप रेल सेवाओं में विस्तार किया जाना आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है और यही कारण है कि प्रत्येक रेलमंत्री हर रेल बजट में नई गाड़िया चलाने, गाड़ियों के फेरे बढ़ाने और उनकी दूरी बढ़ाने की घोषणा करते रहे हैं , जिसके कारण भारतीय रेलो पर और विशेषकर उत्तर रेलवे पर काम का दवाब दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है। जहॉ नई गाड़ियों के संचालन तथा नई रेल लाइनों , शेडों , डिपो में सवारी एवं माल ड़िब्बों के रख–रखाव के लिए अतिरिक्त कार्य बल की महती आवश्यकता है , वहीं दूसरी ओर रेल प्रशासन द्वारा वर्तमान पदों को भी अंधाधुंध सरेण्डर करने की प्रकिया लगातार जारी है , और यह नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन के इस सम्मेलन के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है एवं इस पर अविलंब अंकुश लगाया जाना समय की मांग है।

यह अत्यन्त निराशाजनक है कि भारतीय रेलों पर आउटसोर्सिंग व निजीकरण , जिसकी शुरुआत पहले सीमित क्षेत्रों में विनम्रता एवं आग्रह के साथ की गई थी , वह दिनों –दिन विराट रुप धारण करता जा रहा है और आज परिस्थितियॉ ऐसी है कि वाणिज्य विभाग के अनेको कार्य जैसे ब्रेकवान की लिजिंग , पी आर. एस को निजी हाथों मे सौंपना , कैरिज एण्ड वैगन में सफाई के कार्य को ठेके पर दिया जाना , विद्युत विभाग के अनेको कार्यो को आउटसोर्स किया जाना , रेलवे ट्रैक के रख–रखाव का 50 प्रतिशत तथा वर्क साइड का 75 प्रतिशत से अधिक कार्य ठेके पर कराया जा रहा है। इतना ही नहीं रेलवे कारखानों , शेड़ों इत्यादि में उपलब्ध क्षमताओं का शत–प्रतिशत उपयोग करने के स्थान पर अनेकों कल–पूर्जो को ट्रेड से खरीदने एवं बहुत सी गतिविधियों को ठेके पर संचालित करने का काम हो रहा है। रेलवे के प्रिटिंग प्रेस बन्द किये जा रहे है तथा चिकित्सा –विभाग में डाक्टरों एवं पैरा मैडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति ठेके पर की जा रही है। नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन का यह अधिवेशन , महामंत्री से अनुरोध करता है कि इस दिशा में अखिल भारतीय स्तर पर नीतिगत निर्णय लेकर संर्घष की रुप–रेखा तैयार करके , आउटसोर्सिंग और निजीकरण की बढ़ती प्रवृति पर रोक लगाने के लिएँ प्रभावी कदम उठाया जाय।

उत्तर रेलवे पर विभिन्न कोटियों और विशेषकर संरक्षा कोटियों में जिनमें स्टेशन मास्टर ,यार्ड स्टाफ, ट्रैफिक तथा लोको रनिंग कर्मचारी , सिंगनल अनुरक्षक, तकनीशियन , अधीनस्थ इंजीनियर, ट्रैकमैन इत्यादि शामिल है , के हजारो पद खाली पड़े हैं । नई गाडियॉ लगातार हर बजट में चलाये जाने का कार्य हो रहा है एवं नई रेल लाईने और नयें सयंत्र , शेड़ एवं ड़िपो स्थापित किये जा रहे हैं , परन्तु इनके संचालन और रख–रखाव के लिए आवश्यक पदों की स्वीकृति में ,रेलवे बोर्ड की अनुचित नीतियों के चलते सैकडों बाधाये हैं, जिसके कारण आवश्यक *मानव–बल* की उपलब्धता संभव नही हो पा रही है। यह एक विचारणनीय प्रश्न है कि जहॉ भारतीय रेलों

में कार्य को निष्पादित करने वाले *समुह 'घ' एवं 'ग'* के कर्मचारियो की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, वहीं अधिकारियों की संख्या तुलनात्मक रुप से बढ़ती जा रही है और कामगार : अधिकारी अनुपात जो वर्ष 1996–1997 में 128:1 था वह वर्ष 2006 में **90:1** हो गया। यह एक अत्यन्त विषम परिस्थिति है ,जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल सुरक्षित रेल संचालन पर पड़ रहा है , अपितु वर्तमान रेल कर्मचारी भी बढ़ते काम के चलते तनावग्रस्त एवं अनेकानेक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं । यह अधिवेशन रेल मंत्रालय से इस समस्या के तत्काल समाधान की पुरजोर मांग करते हुए यह अपेक्षा करता है कि इस गंभीर विषय पर *त्वरित कार्यवाही* की जायें।

छठें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के पश्चात अनेको कोटियों में अनगिनत वेतन विसंगतियॉ उत्पन्न हो जाना एक स्वाभाविक प्रकिया है। इसके साथ ही एम. ए. सी. पी. की जो स्कीम *डी. आ. पी. टी.* एवं रेल मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है , उसमें अनको खामियॉं हैं , जिसके कारण कर्मचारियों को इसका समुचित लाभ नही मिल पा रहा है / *उत्पादकता पर आधारित बोनस* की मांग रेल कर्मचारियो ने लम्बे संघर्ष एवं अनेको कुर्बानियॉ देकर हांसिल की है तथा इस पर भी वित्त मंत्रालय की गिद्ध दृष्टि हमेशा लगी रहती है एवं लगातार इसमें कटौती के लिए नये–नये फार्मूले सुझाने का काम किया जाता है। *दिनांक 1.1.2006* से नये वेतनमान लागू हो जाने के पश्चात रेल कर्मचारियों को मिलने वाले सुविधा, मानार्थ एवं अन्य पासों की पात्रता पर लगातार रेल मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श एवं सहमति हो जाने के बावजूद निर्देश जारी करने में अनावश्यक देरी हो रही है । *दिनांक 1.1.2004* के बाद रेलवे में नियुक्त हुये कर्मचारियों पर *नई अंशदायी पेन्शन योजना* लागू की जा रही है , जिसमें न तो *न्यूनतम पेन्शन* की कोई गांरटी है और ना ही , वर्षो के संघर्ष के बाद हासिल की गई , *सामाजिक सुरक्षा* की प्रतिबिंम पारिवारिक पेन्शन की कोई व्यवस्था है। नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन का 31 अगस्त एवं 1 सितम्बर को लखनऊ में आयोजित यह सम्मेलन इन समस्याओं के प्रति अपनी गंभीर चिंता को रेंखाकित करते हुए ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन से इन महत्वपूर्ण मुददो पर तत्काल संघर्ष की रुप–रेखा तैयार करने की अपेक्षा करता है।

नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन का यह अधिवेशन रेखांकित करता है कि छठे वेतन आयोग की विषंगतियां जिनमें , कीमैन , मेट , रनिंग , तकनीकी , संचालन,वाणिज्य, लिपिकीय वर्ग इत्यादि शामिल है एवं रुपयें 4600 ग्रेड पे में कार्यरत सभी सुपरवाइजरों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों को वित्त मंत्रालय से शीघ्र हल कराने , जनवरी 2006 से जून 2006 के मध्य वेतन वृद्धि पाने वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि जनवरी 2006 से लागू कराने , एम. ए. सी. पी. की विषंगतियों को दूर कराने , नये वेतनंमान के आधार पर पास की सुविधा प्रदान किये जाने , संरक्षा आधारित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम (एस आर वी आर एस) लागू किये जाने , रेल कर्मचारियों के बच्चों को रेलवे में भर्ती में प्राथमिकता दिये जाने और रनिंग कर्मचारियों को 36 घंटें में हेडक्वार्टर वापसी की अधिकतम सीमा लागू कराने के लिए माननीय रेलमंत्री के आश्वासन के बावजूद अनावश्यक विलंब हो चुका है , ऐसी स्थिति में हम बहुत समय तक मूकदृष्टा नही रह सकते , और आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन से आह्वान करते है कि वह संघर्ष का फेसला करे , जिसे नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन पूरी ताकत से कामयाब बनायेगी।

यह अधिवेशन उपरोक्त मांगो को शीघ्र मंगवाने के लिए 20 सितम्बर 2010 से 24 सितम्बर 2010 तक सारे उत्तर रेलवे पर जन–जागरण अभियान चलाकर कर्मचारियों को संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए समस्त शाखाओं एवं मण्डलों को निर्देशित करता है।

यह अधिवेशन निम्नलिखित 22 सूत्रीय लम्बित मांगो की ओर रेल प्रशासन का घ्यान आकर्षित करते हुए यह मांग करता है कि इनका समाधान समयबद्ध तरीके से यथाशीघ्र किया जाए।

1 रेल में रेल कर्मियों के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाए।
2 छठें वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न वेतन विसंगतियॉ सीमित समयावधि में दूर की जाए।
3 **MACP** स्कीम की खामियों को शीघ्र दूर किया जाए।
4 तकनीकी कर्मचारियों एवं अधीनस्थ इंजीनियरों को बेहतर वेतनमान शीघ्र दिये जाए।
5 ट्रैफिक एवं लोको रनिंग कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों और कार्य दशा में तत्काल सुधार किया जाए।
6 रनिंग भत्ते को आयकर की कटौती से पूर्णत: मुक्त किया जाए।
7 समस्त रेल कर्मचारियों की उच्च गुणवत्ता की वर्दी एवं समुचित धुलाई भत्ते की व्यवस्था शीघ्र हो।
8 रेलवे कालोनियों , रनिंग रुम एवं कर्मचारी विश्राम गृहों की दशा में व्यापक सुधार किया जाए।
9 बढ़े हुये कार्य एवं नई गाड़ियों के संचालन के लिए आवश्यक अतिरिक्त पदों की व्यवस्था एवं उनको तत्काल भरने के लिए स्थानीय स्तर पर भर्ती व रेल कर्मचारियों के बच्चों को वरीयता के आधार पर नियुक्ति की व्यवस्था शीघ्र की जाए।
10 संरक्षा आधारित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का उदारीकरण कर समस्त कोटि के रेल कर्मचारियों को इसका लाभ शीघ्र दिया जाए।
11 कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय महत्व की रेल निर्माण परियोजना तथा वहा रेल संचालन में कार्यरत रेल कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर प्रोत्साहन योजना तुरन्त लागू की जाए।
12 जो रेल कर्मचारी कश्मीर घाटी में रेल संचालन या निर्माण में कार्यरत है , उनको वहॉ की विपरीत परिस्थितियों के मद्देनजर रेल प्रशासन 20 लाख रुपये की बीमे की सुविधा मुहैया कराये।
13 वर्षो से लम्बित "उच्च स्तरीय समिति" का गठन कर संरक्षा कोटियों में कार्यरत रेल कर्मचारियों के कार्य के घंटों में तत्काल कमी की जाए।
14 महिला रेल कर्मचारियों के लिए कार्य स्थल पर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध काई जाए तथा बच्चों की देखभाल के लिए शिशु पालन केन्द्र बनाये जाए।
15 रेलवे चिकित्सालय में उचित गुणवत्ता की औषधियों , समुचित संख्या में चिकित्सको एवं पैरा मेडिकल कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
16 ऐसे दुर्गम क्षेत्रों जहॉ रेलवे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही है वहा कार्यरत रेल कर्मचारियों को अन्य केन्द्रीय एवं निजी कर्मचारियों के सामान मासिक चिकित्सा भत्ता का भुगतान किया जाए।
17 कारखानों, शेड़ो एवं ड़िपो में कार्यस्थल की दशा सुधारी जाए एव आधुनिक तकनीकी आधारित औजारों की शीघ्र व्यवस्था की जाए।
18 ट्रैक मशीन के कर्मचारियों के लिए समुचित साइडिंग एवं 21 दिन प्रतिमाह की रोस्टर की व्यवस्था अविलंब की जाए।
19 ट्रैकमैनों को उच्च गुणवत्ता की वर्दी , नवीनतम तकनीकी के औजार एवं रेलवे लाईन के किनारे रेस्ट शेल्टर की व्यवस्था की जाए।
20 ग्रुप सी से ग्रुप बी में प्रोन्नति अविलंब की जाए।
21 1 जनवरी 2006 से नये वेतनमान लागू होने पर ओवरटाइम भत्ते का भुगतान अति शीघ्र किया जाए।

22 रेलवे लाइन के किनारे की भूमि को ट्रैकमैन आदि को कृषि हेतु आवंटित करते समय जो धनराशि उनसे ली जा रही है, वह न्यायसंगत नही है क्योकि वह रेलवे की भूमि में अनाज उत्पन्न करके न केवल देश का भला कर रहे है बल्कि रेलवे की भूमि की रक्षा भी कर रहे है। अतः यह धनराशि लेना बन्द किया जाय।

भविष्य की कार्ययोजना

उपरोक्त जांयज लम्बित मांगो का शीघ्र हल कराने के उद्‌देश्य से रेल प्रशासन एवं रेल मंत्रालय पर इसके लिए दबाव बनाने हेतु हमे निरन्तर संघर्षरत रहने की आवश्यकता है और उत्तर रेलवे के प्रत्येक रेल कर्मचारी को जिसमें युवाओं एवं महिलाओं का योगदान भी विशेष महत्व का है, यूनियन की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में जोड़कर रखना आवश्यक है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से कमवार निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।

1 पूर्व निर्णय के अनुसार प्रत्येक शाखा एवं मंडल स्तर पर *युवॉ कमेटियों एवं महिला कमेटियों* का गठन करके उनके नियमित बैठके आयोजित किया जाना संगठन के हित में अति आवश्यक है। अतः सभी शाखायें इसका गंभीरता से कियान्वयन सुनिश्चित करें।

2 ए. आई आर एफ द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन ने विगत अवधि में ट्रैक मशीन कर्मचारियों, पुछताछ एवं आरक्षण कर्मचारियों ,ट्रैफिक एवं लोको रनिंग कर्मचारियों तथा रसायन एवं धातुविज्ञ कर्मचारियों के सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित करने का काम किया है परन्तु अभी भी अनेकों महत्वपूर्ण कोटियों के मंडल स्तरीय एवं केन्द्रीय स्तरीय सम्मेलन आयोजित करना समय की मांग है और इस दिशा में हमें त्वरित कार्यवाही करने का आवश्यकता है।

3 युवाओं को पूरे वर्ष का कार्यक्रम सुनिश्चित करके उन्हें यूनियन की नान–बार्गेनिंग गतिविधियो में व्यस्त रखने से संगठन को उनका महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा और इसके लिए कार्यकम की ठोस रुप–रेखा बनाई जाय।

4 ट्रेड यूनियन शिक्षा , यूनियन के लिए अत्यन्त महत्व का विषय है और शाखा से लेकर मंडल स्तर तक इसका चरणबद्ध आयोजन संगठन के लिए अति आवश्यक है। इस दिशा में भी शीघ्रता से आवश्यक कदम शाखा एवं मंडल स्तर पर उठायें जाय।

5 शाखाओं द्वारा डेलीगेट स्तर की बैठके वर्ष में कम से कम 4 बार आयोजित करना अति आवश्यक है ताकि संगठन को जीवन्त एवं सकिय बनाया जा सके, अतः शाखायें इस दिशा में कोई कोताही न बरतते हुए शीघ्र ही ठोस कदम उठायें।

6 प्रत्यके डेलीगेट एवं सकिय कार्यकर्ताओं को नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन की मासिक पत्रिका के सदस्य अनिवार्य रुप से बनाने के लिए शाखायें गंभीरता से प्रयास करे।

7 प्रत्यके शाखा स्तर पर *"वालेन्टियर कोर"* ग्रुप का गठन अनिवार्य रुप से किया जाय और इसकी नवीनतम जानकारी केन्द्रीय कार्यालय को , कोर ग्रुप के समस्त सदस्यों के नाम एवं टेलीफोन नम्बर के साथ 1 माह के अन्दर अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराये जाय।

8 केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि में विभिन्न मदों के लिए आवंटित धन का मंडलो/शाखाओं द्वारा समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु मंडल एवं शाखा स्तर पर आवश्यक कदम उठाये जाय ताकि इसका वास्विक लाभ कर्मचारियों तक पहुंच सके।

9 पदों के अंधाधुध सरेण्डर , नियमित कार्य की आउटसोर्सिंग /निजीकरण का शाखा स्तर पर पुरजोर विरोध जारी रखा जाय ताकि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके।

10 विभिन्न लम्बित मांगो जैसे पास की पात्रता , संरक्षा आधारित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आदि पर रेल मंत्रालय द्वारा पत्र जारी करने में की जा रही अनावश्यक देरी के विरोध में इस सम्मेलन के पश्चात शाखाओं एवं मंडल स्तर पर विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित कर लोगो को संघर्ष के लिए जागरुक किया जाय।

11 ए.आई.आर.एफ. का फैसला कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित किया जाय, को मूर्तरूप देने के लिए एक कार्ययोजना बनाई जाय।

12 मेट्रो सहित तमाम रेल परिसरों में कार्यरत कामगारों को संगठित करने की योजना तय कर उसे अमली जामा पहनाया जाय।

13 विभिन्न विभागों में कार्यरत रेल कर्मियों के काम के घंटे एवं कार्यदशाओं का यूनियन ग्रास रुट पर अध्ययन कर भविष्य की संघर्ष योजनाओं में इसे शामिल करे।

14 केन्द्र से निरंतर निर्देश जारी किये जाने के बावजूद भी अनेको शाखायें शाखा परिषद की नियमित बैठके आयेजित करने तथा समय पर त्रिवार्षिक चुनाव सम्पन्न करने के प्रति उदासीनता का रवैया अपना रही हैं जोकि संगठन के हित में नही है। सभी शाखायें नियमित रुप से शाखा परिषद की बैठके आयोजित करे और यूनियन के संविधान के अनुसार समय पर चुनाव सम्पन्न कराकर इसकी सूचना मंडल तथा केन्द्रीय कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करे।

15 नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन एक स्वत्रंत ,स्वावलम्बी तथा लोकतांत्रिक संगठन है और इसके लिए आवश्यक है कि हमारी प्रत्येक शाखा अपने पूरे कैडर को किसी भी अग्नि परीक्षा जिसमें गुप्त मतदान द्वारा मान्यता शामिल है , के लिए हमेशा तैयार रखने का काम करे।

प्रस्ताव संख्या –2

कश्मीर घाटी में रेल

कश्मीर घाटी में रेल सुविधायें स्थापित करना एक राष्ट्रीय महत्व का विषय रहा हैं जिससे राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने और उस क्षेत्र का विकास होने में भारी मदद मिलना अवश्यसंभावी है। उत्तर रेलवे के कर्मचारियों ने कश्मीर में रेल लाइन बिछाने की परियोजना को मूर्तरुप देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और तमाम दुर्गम क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों के बावजूद अपनी जान पर खेलकर कार्य किया है। इस परियोजना पर कार्य करते हुए कुछ रेल कर्मियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी , परन्तु हमारे कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके परिणामस्वरुप *दिनांक 11.10.2008* को कश्मीर घाटी में भारत के प्रधानमंत्री ने नवगॉव से अनंत्तनाग तक रेलगाड़ियों के संचालन की ऐतिहासिक शुरुआत की। वहॉ पर रेल संचालन मे कार्यरत हमारे सैकड़ों रेलकर्मी साथी अभूतपूर्व उत्साह एवं जीवट का परिचय देते हुए इस कार्य को बखूबी करने का काम कर रहे है।

कश्मीर में रेल संचालन शुरु होने के बाद मैं स्वयं अपने तमाम पदाधिकारियों , जिनमें फिरोजपुर एवं हेडक्वार्टर मंडल के मंडलाध्यक्ष एवं मंडलमंत्रियों के साथ –साथ , साथी एस. के. राणा , सहा महामंत्री व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष , साथी वाई. के. शर्मा के अलावा जम्मू शाखा एवं निर्माण शाखाओं के पदाधिकारी भी शामिल थे, के साथ कश्मीर घाटी गया और इन रेल गाड़ियों में यात्रा कर रहे कश्मीरियों के चेहरे पर अदभुत चमक को देखा। यही नही *दिनांक* **05-07-2009** को श्रीनगर स्थित बडगाम में नारदर्न रेलवेमेन्स यूनियन द्वारा आयोजित रैली में वहॉ कार्यरत रेल कर्मचारियों का उमड़ा जनसमूह इस बात को दर्शाता हैं कि उनके लिये यूनियन कितनी महत्वपूर्ण हैं और वह इससे कितना प्यार करते हैं। हमें लगता है कि यह रेल प्रोजेक्ट हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की एक मिसाल है। कश्मीर घाटी में स्थापित की गई रेल सेवा वहां के निवासियों के लिए बहुत ही सुगम एवं सस्ती है , जिसमें केवल पुरुषो से 12 रुपये किराया लिया जा रहा है और महिलाओं तथा बच्चों के लिए यह सुविधा मुफ्त है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विघटनकारी तत्वों एवं विदेशी ताकतो को कश्मीर घाटी का विकास रास नही आ रहा है , और यही कारण है कि विगत दिनों वहा अशांति का माहौल पैदा करने की पुरजोर कोशिश कुछ अराजक तत्वों के सहयोग से करने का काम किया गया , जिसके चलते वहां सुचारु रुप से कार्य कर रहा रेल संचालन बन्द होने की स्थिति में आ गया।

साथियों , इस समय कश्मीर के हालात काफी खराब हैं , क्योकि हाल ही में *सोपोर* रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ और वहाँ के पावर केबिन में आग लगा दी गई तथा जब *बडगाम* में रेल कर्मियों की कालोनी पर हमला हुआ और घबराये रेल कर्मी साथियों के फोन आये तो बहुत ही सदमा लगा। रेलों पर हमला वास्तव में देश के विकास पर हमला है और यह देश के दुश्मनों की सोची –समझी चाल हो सकती है ,साथ ही उन ट्रांसपोर्टरों की भी जिनके व्यापारिक हितों पर रेल चल जाने की वजह से चोट पहुंची है। ऐसे लोग एकता की इस मिसाल को कायम नही रहने देना चाहते और हर समय वहां की रेल ,यात्रियों और रेल कर्मचारियों पर आघात करते रहते है , जिससे हमारे देश की एकता बरकरार न रह सके।

एन. आर. एम. यू. का यह अधिवेशन *कश्मीर घाटी* में घटित हुई इन दुखद घटनाओं पर खेद प्रकट करता है तथा यह मांग करता है कि कश्मीर घाटी में रेल सेवा को पुनः बहाल किया जाय और वहाँ के रेल–कर्मियों को व्यापक सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान की जाए और ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जिससे कश्मीर घाटी की रेल, विकास और एकता की प्रतीक बन सके।

उपरोक्त प्रस्तावों को कामरेड एस के त्यागी,मंडलमंत्री हेडक्वार्टर मंडल द्वारा पेश किया गया जिसका समर्थन कामरेड दलजीत सिंह मंडलमंत्री फिरोजपुर ने किया एवं बहस के बाद इन प्रस्तावों को अधिवेशन द्वारा सर्वसम्मति से पारित घोषित किया गया।

****